हो तो देखिए मीटिंग बुलाकर बात कर सकते हैं और बुलाते हैं जैसा कि हमारे यहां हुआ । यह परिषद बनने के पूर्व सारे देश के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर्स का भी राय मश्विरा हुआ और बहुत छानबीन करने के बाद यह आपके पास राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का विधेयक हम ला रहे हैं । सभी लोगों से, यहां तक कि स्वयसेवी संस्थाओं से भी हमने परामर्श किया और आपकी जानकारी के लिये मैंने सोचा कि मैं आपको कह दूं : इस-लिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो विधेयक है, यह निर्दोष है, निश्छल है, जनसेवी है, निर्बल-उन्मुख है और विकलांगों के प्रति जो सेवा हो सकती है वह उसमें निहित है । क्योंकि अब तक होता क्या था कि जो भान-गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस के तत्वाधान में शिक्षा प्राप्त करके, ट्रेनिंग प्राप्त करके जो डाक्टर बनते थे या प्रैक्टीशनर बनते थे या प्रोफैशनल होते थे उनके अन्दर बहुत सा दोष का हमारे पास आरोप आया उनकी गलतियों का, इसी के परिणामस्वरूप यह परिषद बन रही है और इसके अन्तर्गत यह इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं कि यहां से जो प्रमाणित प्रशिक्षित प्रशिक्षण के बाद निकलेंगे वह हमारे विकलांग भाईयों के लिये एक अच्छे मुफीद डाक्टर के रूप में, प्रोफैशनल के रूप में, प्रैक्टीशनर के रूप में सेवायें दे सकेंगे ।

इन सारी बातों के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें । मैं सदन से आग्रह करता हूं कि कृपया इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Now I shall put the motion to vote.

The questions *id*

That the Bill to provide for the constitution of the Rehabilitation Council o* India for regulating the training of rehabilitation professionals and the maintenance of a Centfal Rehabilitation Register and for matters connected therewith o* incidental thereto, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN; I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 30 and *the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री सीताराम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाये ।

The question was put and the motion was adopted.

THE COAL MINES (NATIONALIS-ATION AMENDMENT BILL, 1992

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHR] S. B. NYAMAGOUDA). Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration.

There is a need to augment the generation of power in the country today in order to provide the basic input of energy to the fast developing industrial and technological sce-nario. In order to allow the private sector to set up power plants, the Indian Electricity Act. 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 have been amended. This has facilitated private sector investment in setting up additional power generation capacity during the Eighth Plan.

The successful participation of private sector in power generation can be ensured only when adequate fuel linkages are provided to the power stations proposed to be set up. Coal is by and large the dominant source of commercial energy in the country. Therefore, ensuring optimal coal linkages is the most essential first step

[Shri S B. Nyamagouda]

towards successful implementation of the policy of the Government. To meet the additional demand of coal and keeping in view the problem of resource availability, the Government has decided to liberalise its policy re. lating to coal development and allow the private sector power generating units to develop captive coal mines for meeting their own requirements of coal.

Similar necessity has been felt to permit setting up coal washeries to augment supply of clean coking coal to steel plants and other industrial users. The beneficiation of non-coking coal will -ensure greater efficiency of the power stations and less burden on the railway transport system by way of preventing the transport of extraneous material. Coal India Limited will not be able to set up the required number of washeries in the public sector. Apart from the demands generated in the power sector, other industries like cement, sponge-iron etc., will also require coal mining linkage for their captive end use. The Government would consider the requirement of such industries from time to time and allow specified industries to take up coal mining activities for captive purposes.

Hon. Members may recall that the coal mines in the country have been nationalised by virtue of the provisions of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973. By the amendment of this Act in 1976, sub-section (3) of Section 3 was inserted which laid down that no person other than the Central Government or a Government Company or a Corporation owned, managed or controlled by the Central Government shall carry on coal mining operation in India in any form. The only exception gran. ted under this provision was to the companies engaged in the production of iron and steel. There was also a provision for granting sublease to any parties in a case where the reserves of coal are in isolated small pockets not amendable to scientific and economic development and not requiring transport by rail.

It has now been proposed in the Bill to amend sub-section 3 of Section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 as amended in 1976 in order to allow a company engaged in generation of power, washing of coal obtained from a mine or other end uses as may be notified by the Central Government, to take up coal mining operations. This will be in addition to a company engaged in the production of iron and steel which has already been provided under the statute. With this amendment, the power seotor as well as other industries will be assured of necessary coal linkages for their captive consumption. The setting up of coal. washeries in the private sector will also be facilitated.

The nationalisation of coal mines was undertaken to rectify the ills of private sector management. Prior to nationalisation, coal mining was characterized by unscientific mining, non-maintenance of safety measures, payment of less than minimum, wages to the workers etc. All the controls regarding approval of mining leases, environmental clearances, safety and welfare measures, etc., as provided under the rules will continufe^ to be enforced. Private Sector parties would have to take necessary steps for obtaining mining lease, environ-mental clearance, acquisition of land for the infrastructural facilities and permission from the Directorate -General of Mines Safety for opening the mine. The Coal Controller will foe further empowered under the Coal Mines (Conservation & Development) Act to exercise adesuate supervision over the coal mines *to* ensure safety and scientific exploitation of the mineral resources.

The proposed amendment would thus enable the private sector to augment our industrial production.

With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस सदन में पहली बार बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए यह जो बिल अभी सदन के सामने रखा गया है, उस पर विचार करने के पूर्व मैं इस सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट जोकि 1972 में पास किया गया था उसके प्रिअम्बल में कहा गया था कि—

(a) protecting and conserving;

(b) promoting scientific development;

(c) to meet the growing requirements of the iron and' steel industry;

(d) for matters connected therewith or incidental thereto.

इसी तरह कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, 1973 की धाराओं में कहा गया था कि—

(a) Reorganization and reconstruction of the coal mines;

(b) to show the rational, coordinated and scientific development and utilisation of coal^ resources;

(c) to distribute, disburse as to best subserve the common good;

(d) for matters connected therewith or incidental thereto.

अब विचार इस बात पर करना है कि जो प्रिअम्बल में कहा गया था कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट के बारे में अब विचार इस बात पर करना है कि जो प्रीएम्बल में कहा गया था कोल माइन्स नेशनल एक्ट के बारे में, कोकिंग कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट के बारे में, बीस साल बाद क्या हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पहले कहा गया था प्रोटेक्टिंग एण्ड कंजर्विंग, आज 44 मिलियन टन कोकिंग कोयला इस देश में पैदा किया जाता है, कम से कम स्टेटिस्टिक्स यह बताते हैं, जबकि हमारे स्टील प्लांटों को केवल 9 मिलियन टन कोयला सप्लाई होता है बाकी कोकिंग कोयला, जो धातु शोधक कोयला कहा जाता है वह नन-मेटालोजिकल व्यवहार के लिए दिया जाता है। क्या यह कंजरवेशन है ? क्या यह नेशनलाइजेशन एक्ट का जो परपज था वह पूरा किया गया है ?

दूसरी बात, महोदया, आज भी स्टील प्लांटों की कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4.6 मिलियन टन से ज्यादा कोयला आयात किया जा रहा है, जिसमें साढ़े सात सौ करोड़ से अधिक रुपया लग रहा है। हर साल देश को आने वाले समय तक, जैसा कि प्रोजेक्शन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में है, सन 2000 ईसवी तक कोयला आयात करना पड़ेगा। यहां तक साइंटिफिक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं आपकी मार्फत इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं उस हिस्से से आता हूं, जहां कोकिंग कोल की माइन्स हैं, धनबाद झरिया कोल फील्ड जिसे कहते हैं, अभी तक आज बीस साल बाद एक भी डीप शाफ्ट नहीं खोदा गया है।

महोदया, कोयला तीन प्रकार का निकाला जाता है। एक वह कोयला, जो सरफेस को हटाकर माइनिंग किया जाता है, उसको ओपेन कास्ट माइनिंग कहते हैं। दूसरा वह कोयला, जो इनक्लाइन से डवलप किया जाता है, जिसको इनक्लाइन माइनिंग कहते हैं। और, तीसरा कोयला वह है, जो हजारों फीट नीचे रहता है उसको पिट के जरिए निकाला जाता है और जिसको पिट माइनिंग कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इजीएस्ट

[श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल]

फोर्म आफ माइनिंग है वह ओपेन कस्ट माइनिंग । उसमें इस देश का 18 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ हैं। जो रीयल सेन्स में साइंटिफिक होना चाहिए, उसके प्रयत्न हो रहे होंगे, बाकी उस दिशा में कोई सही कदम नहीं उठाया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अंडरग्राउंड माइनिंग में अभी तक कोई डवलपमेंट नहीं है । क्वालिटी जो कोल नेशनलाइजेशन के पहले कोल वाशरी को 22 परसेंट ऐश फीड किया जाता था, आज एवरेज ऐश उसका 30 परसेंट है । क्या यह साइंटिफिक डवलपमेंट है ?

इसके अलावा, अभी पिग आयरन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया । उसको धातुशोधक कोयले की जरूरत है। असल में धातुशोधक कोयले से पहले कोक बनता है और कोक स्टील प्लांट में भी, पिग आयरन बनाने में भी और देश की बहुत सी इण्डस्ट्रीज में काम में जाता है । उसकी इस देश में बहुत शार्टेज है । इस बिल में उस कमी को मीट करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए को ई प्रावधान नहीं है। पिग आयरन आज इम्पोर्ट हो रहा है, शार्टेज है इसकी कन्ट्री में । यदि उसको इस देश में बनाने के लिए कोक लाना पड़े तो देश को हर साल 145 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा फारेन एक्सचेंज के रूप में । कोकिंग कोल के लिए 750 करोड़ रुपया और कोक के लिए 145 करोड़ रुपया, इस तरह यह 895 करोड़ रुपया देश को आने वाले हर साल में खर्च करना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोयले के रिसोर्सेज है। मैं सदन का ध्यान आपकी मार्फत इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोल माइन्स को मिलजुल कर डवलप करें, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि मिलजुल कर यदि काम किया जाए तो हम लोग कोयले के मामले में स्वावलंबन प्राप्त कर सकते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

अब नन-कोकिंग कोयले की बात पर आता हूं । महोदया, पहले कोयले की जो आखिरी सीमा निर्धारित थी क्वालिटि के बारे में, उसमें 35 परसेंट ऐश का कोयला, उससे ऊपर होने वाला नन मेंडेबल माना जाता था। इसका एक्ट में प्रावधान था और यह कोल बोर्ड के कानूनी अधिकार के तहत था। आज उसको हटाकर 54.60 प्रतिशत ऐसा कोयला भी कोयले की केटोगरी में आ गया । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ईस्टर्न जोन में कोयला है, यदि उसको ट्रांसपोर्ट करके वेस्टर्न भाग में ले जाना पड़े यदि किसी को एक हजार केलोरी की जरूरत है, यदि उसको दो तीन टन कोयला ले जाना पड़े, तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट केपिसिटी है, जो कि बहुत कम है, उसका गलत यूटिलाइजेशन होता है, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं होता है। उससे बेसिक एनर्जी का कॉस्ट बढ़ता है । थोड़ी सी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी का खर्च होता है । यह जो बीस हजार करोड़ रुपया आज तक इस इन्डस्ट्री में देश में डाला गया, इसके साथ-साथ इस देश की सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लायमेंट इसके बारे में भी सोचना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसी नीति अपनाई गई कि आज जिस इडस्ट्री में 20 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है उसमें एम्प्लायमेंट पोटेंशियल जीरो है ? आज एक भी आदमी को उस इडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। इसका कारण है हैवी मेकेनाइजेशन और फारेन कोलाबरेशन । जब कि उस तरह की मशीनें हम लोग, कुछ हिस्से में अवश्य जरूरत है जहां कोलाबरेशन भी जरूरी है इम्पोर्ट भी जरूरी है, लेकिन ऐसी मशीनें हैं जो हम देश में बना सकते हैं और स्वावलबी बन सकते हैं। इस संदर्भ में, महोदया, मैं आपका ध्यान चीन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जहां 900 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया जाता है । उसमें से 275 मिलियन टन कोयला 20 हजार छोटी-छोटी कम्यून माइन्स से पैदा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी का कोयला प्रोड्यूस करती है। भारत में इतना कोल रिसोर्सेस होने के बावजूद अभी तक कोयले के मामले में हम

लोग स्वावलंबन प्राप्त नहीं कर सके हैं। आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हू कि सी०आई०एल० का कभी तक केवल एकोमोलेटेड लास 2498.98 करोड़ हुआ है, केवल इस साल 253 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बी०सी०सी०एल० में 4.5 मिलियन टन के करीब कोयले का शार्टेज है जो कि स्टाक दिखाया गया है कि कोयला वहां नहीं है। सी०सी०एल० में 2.5 मिलियन टन का शार्टेज है जो कि वहां नहीं है। एस०ई०सी०एल० महानदी बेसिन, इसमें भी अभी 3.5 मिलियन टन कोयले का शार्टज है। डब्लू०सी०एल० में 0.5 मिलियन टन की शार्टेज है और ई०सी०एल० में 2.5 मिलियन टन की शार्टेज है जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए होती है।

मैं माननीया मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत देरी के बाद एक सही दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह कदम कुछ रोककर बढ़ाया है, जिस प्रकार खुले-आम इसको करना चाहिए, नहीं किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोक बनाने के लिए जो कोयले की जरूरत है, आपने बाजरी को दे दिया, आपने आयरन एण्ड स्टील को दे दिया, लेकिन पिग आयरन का क्या होगा? आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्री में, पिग आयरन इंडस्ट्री में पहले कोक बनेगा• तब उसका युटिलाइजेशन होगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह जो धारा है

• "washing of coal obtained from mine Eor production of coke"—

इसको अमेंड किया जाना चाहिए तब हम लोग कम से कम साल में 4-5 सौ करोड़ रुपया देश का जो फारेन एक्सचेंज आता है, उसको बचा सकते हैं। मैं फिर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके आने के बाद काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है।

इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और फिर से आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): While supporting the Bill I want to say a word of caution to the Government. Steel, coal and power are the infrastructural facili ties for the development of the country. It is for the first time that we have taken a decision to privatise this industry and the main reason given here is that Coal India and Neyveli Lignite Corporation are experiencing a resource constraint. This is the main reason for this amending Bill. Coal mining for power generation is secondary. I think at least with regard to infrastructural items, it was a deliberate and cautious step on the part of our forefathers to see that these infrastructural facilities are retained by the Government through the public sector undertakings. Only in exceptional cases these were given to the private sector. But now we are opening a pandora's box. There was nothing wrong if coal could continue to remain under the public sector. They could supply the coal to the people who come up for power generation. Then, I find, no proper explanation has been given even in the introductory speech by the Minister as to why they are clubbing coal mining with power generation. Why can't you bifurcate these two items? Power generation is quite a defferent field. You are supplying coal to so many thermal plants. Coal mining a, an independent activity is going on. I don't understand why they are clubbing these two things?

Anyway, resource constraint is the main or the only reason for privatising coal mining, and just because we are not able to make a headway in power generation, we are inviting private people, even foreign agencies and by inviting NRIs or foreign companies for power generation, we are handing, over coal production to the foreigners. I was listening to the statement ma-d'e by the Minister. He talked

[Shri H. Hanumanthappa]

of Government control over this activity. I don't know how much control the Government will be able to exercise over the private companies. Even this morning we had a question when it was said that arrears running into crores of rupees are there to be recovered and the company is still allowed to invest outside the country. I feel once these things go out of hand, it will be very difficult for you to exercise any control over them as you have experienced in Ayodhya where you are not able to enforce the court orders, and still the things are going on, and you have become incapacitated. That is why I started with a word of caution.

I personally feel that infrastruetu-ral activties should have been with the plublicj sector undertakings and with the Government. But the Government thinks that we will be able to augment production and reduce the shortage. At the same time we are not able to maintain a regular (supply of cocl from our collieries and coalfie'd's. We are unable to mobilise the resources and that is why the Government thinks that this step will add to generation of power and will be helpful in the overall development of the industry.

Madam, both the Coal Ministers came to my State end inaugurated some coal depots etc. Just after two days we saw the headlines in the papers that our thermal unit is closed for want of supply of coal; the fourth unit cannot function because of non-supply of coal and the third unit was suffering from something else and the second unit had to be closed because an amount of Rs. 18 crores was due. All these things happened in just two days after the Minister opened the coal d'epots in my State. Just four days before our Coal Minister had made a statement that our Raichur thermal plant will not suffer for want of coal and its generation will continue. But just after four-five days, the thermal plant had to be i closed. I think this needs some monitoring system. There is something wrong somewhere. The infrastructure which is available is not properly used because of lack of co-ordination. This is one thing. The other thing is lack of resources. This is the reason given for handing over the infrastructure activities to the private sector. That is where I uttered a word' of caution when I began my speech.

With this word of caution, I support this Bill because this is a small am endment. You want to allow certain types of companies to take up coal mining for their captive end use. You have already permitted it in the case of iron and steel. Now, those who are putting up power generation pro jects can also start mining activity. Then, one who washes coal can also start mining activity. Lastly, the Central Government may. by notification, specify those to whom they want to hand over. The control of these activities...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Then, what will remain in the public sector?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: That is what I am saying. The Coal India Limited and the Neyveli Lignite Corporation are in the public sector. They say 'We have no resources.' They say 'We are not able to develop'. Therefore, you say you are hand'ing it over. The Government has a good intention that power generation should be stepped up. I support it, but, as I said with a word of caution that we arr reversing the policy that we have followed all these years. Now, we are allowing the private sector to undertake these infrastructure activties. We know how we have been dictated to by the private sector, wherever they are in a dominant position. We have even been questioned in both the Houses about our dependency about our not being able to have control on them.

I feel that this amendment, where Parliament is giving power for transfer of coal fields to private companies setting up power generation projects, will land the Government into trouble, adding further problems in respect of our infrastructure necessities, which will, ultimately, tell upon the industrial development of our country. With this word of caution, I support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Shri Digvijay Singh. He is not here. Shri Madhavan.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, I welcome the speech of Mr. Hanumantha-ppa, warning the Government.

This Bill is against the objectives of the principal Act, the Coal Mines Nationalisation Act of 1973. The principal Act was piloted in this august House, in 1973, by the great labour leader of Tamil Nadu, with some laudable objectives. Now, the present Bill,—a Bill to denationalise, or, hand over coal mines to the private sector,—has been brought forward by the Labour Minister who is in charga of Coal also. The then Minister, the late Mr. Mohan Kumaramangalam, who piloted the legislation, the principal Act of 1973, outlined its objectives. I quote his words. He said:

> "Coal is really the crucial source of mineral wealth in our country. During the period! of absolute *laissez faire,* profit was the primary consideration, safe methods were in the picture only here and there and national interests were completely forgotten.
>
> This legislation is brought, in order that the ownership and control of such resources are vested in the State and thereby so distributed as best to subserve common good."

Now, t*he* present Government has decided to hand over the coal mines to the private sector. The reason mentioned in the Statement of Objects and Reasons, as pointed out by Mr. Hanumanthappa, is resource constraint. I would like to ask the hon. Minister. Is this the only reason? The Government has given some other reasons for its failure in the nationalised coal sector. I would like to refer to the survey report submitted to the Government. The Public Sector Enterprises Survey Report has analysed this aspect, why there is failure in the nationalised coal sector. I quote:

> "The main reasons for slippage in implementing the capital projects are land acquisition, delay in supply of equipments, change or finalisation of technology, ad'verse geomining condition, poor performance of turnkey contract."

The poor performance is not so In all Coalfield companies. I am proud to say that in Tamil Nadu, Neyveli Lignite Corporation has earned a record profit of Rs. 95.24 crores in 1990-91 the highest recorded for any year since inception.

Hence resource constraints need not lead to allowing international capitalists to exploit our natural resources.

The most objectionable part of the Government's action is to throw open the country's natural scarce resources, coal fields, to foreigners, multinationals. The hon. Minister has stated in his reply to my question, I quote:

> "... the Indian side had requested the French side to consider the possibility of assisting India in the setting up of an integrated coal project consisting of an underground mine, washery and a captive power plant...
>
> The Indian side also proposed to explore the possibility of exporting coal with French assistance."

[Shri S. Madhavan]

What is the necessity? Only Indian Workers are toiling in our coalmines. What do you want from the multinational companies? Is it technology and machinery? For these, we are selling our natural resources. This is our development after 45 years. The former Congress Government threw the Indian capitalists out from our coal fields. Now, the present Congress Government is throwing open our doors to international capitalists. If the Government wants to allow the multinationals to explore our scarce natural resources, they will ask to control the price of coal and also tha distribution of coal at their discretion. This had happened, when the Government approached multinational?, for exploration of oil fields, they wanted distribution rights also. The same thing is going to happen in the coal industry. The Government wants foreigners' help to export coal. Coal India has sent delegation to promote export of coal to SAARC countries. The Government plans to export 4 lakh tonnes during this year.

Our own thermal plants are suffering for want of coal. Thermal plants in Tamil Nadu have to manage with a few days' stock often. In fact, they demand import of coal from Australia. The Government of India once allowed Tamil Nadu Government to import coal from Australia. The hon. Minister must explain these conflicting interests.

I am afraid, this new policy of opening the dbors to multinationals will create shortage of coal for our own thermal plants. The Government must clarify whether thefmal plants from some States like Tamil Nadu have to depend upon private sector coal fields in future. What are the future arrangements to supply coal to the State-owned thermal plants?

Now I would like the hon. Minister to consider certain legal aspects of this Bill. I feel, the present amendment of section 3, allowing private sector participation, is against the object of the principal Act. The preamble of the principal Act of 1973 reads, I quote:

> "An Act to provide for acquisition .. .in order that the ownership and control of such resources are vested' in the State and thereby so distributed as best to subserve the common good."

Further, there is a specific declaration as to the necessity of the Union Government's control under section 1A of the principal Act. It reads, I quote:

> "it is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of coal mines."

This section was specifically introdu-CE'd in 1976 to get the constitutional protection for nationalisation of coal fields under article 31C. So I feel that the present Amendment Bill cannot be passed without amending the preamble and section 1A of the principal Act.

One more legal aspect is the definition of a 'company'. 'Company' has been defined in the principal Act. It will include private, public and foreign companies. After the denationalisation of coal fields^ there is every possibility of private companies dominating the coal distribution. This wiU adversely affect the State-owned thermal plants. So, I suggest that such companies, even Government-owned companies, must be public limited companies. And in every such public limited company, the Central Government or the State Government must hold equity shares of not less than 26 per cent. This will help the Government control and regulate the price and distribution of coal and fulfil the Government's social obligations. But if you are going to leave the price and distribution of coal to the private sector to be decided according to the market forces then I warn that our

own Slate-owned thermal plants will be ruined.

Thank you Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Suresh Pachouri.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA (Uttar Pradesh): Madam, Mr. Digvijay Singh is here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I had already called his name and marked him absent.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA: Now he has come back.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): But I can't call him in thj middle.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Madam, when I left I was told I was No 7. When I came back I was told I was No. 3.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): But there is no other speaker from Janata Dal. No. 3 is Janata Dal, No. 5 is CPI (M). There are no other speakers. They have not given the speakers' names at all.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, you are very kind in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I have no problem but I can't call him now. I will have to call him in the end.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA: They were on *dharna.* That is why he could not come here. .. . *(Interruptions)* . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No no, we don't want to hear why they were sitting on *dharna.* We have got to hear on Coal Mines. ...*(Interruptions)* . . We worked the whole morning. ... *(Interruptions)...It* is not on the agenda. ... *(Interruptions)...* Dr. Jain, please let him speak. ... *(Interruptions)* . ..

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1992 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसी प्रकार का एक एक्ट 1973 में आया था जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ता ने किया है । जो बिल माननीय मंत्री जी ने एक लम्बे समय के बाद लाए हैं यह अत्यंत सामयिक है और आज जिन परिस्थितियों का सामना हमें कोल सैक्टर में करना पड़ रहा है उसके अनुकूल है इसलिए यह बिल बहुत उपयोगी है । कोल इंडिया लिमिटेड पब्लिक सैक्टर में कोल का उत्पादन है । और इसमें लम्बे समय से साधनों का अभाव महसूस किया जा रहा था । विद्युत उत्पादन के लिए यह जरूरी है कि कोयला खान अधिनियम, 1973 का संशोधन किया जाए और यह संशोधन रूप बिल के रूप में माननीय मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है और इस का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं । सरकार ने पूर्व में भी निजी क्षेत्र की विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने की इजाजत दे दी है । निजी क्षेत्र की भागीदारी दिए जाने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा चुका है । कोयला विधेयक में ग्रहित उपयोग के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने के बारे में विचार किया गया है अर्थात् उन्हीं पार्टियों को जिन्हें विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए अनुमति दी गई है इन विद्युत संयंत्रों को फीड किए जाने के लिए कोयला खानों का परिचालन करने के लिए अनुमति दी जाएगी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 3 हजार मैगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है । यह बिल जिस रूप में यानी संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इसके प्रस्तुतिकरण से यह जो क्षमता, जिसका मैंने जिक्र किया है इसको फीड

[श्री सुरेश पचौरी]

किए जाने के लिए निजी क्षेत्र में उपयुक्त खानों को खोला जा सकेगा ।

ऐसा मंतव्य जाहिर किया गया है । इसी तरह निजी क्षेत्र में कोकिंग कोल और नान-कोकिंग कोल की ढुलाई करने के लिए वासियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन इससे दिया जा सकता है । साथ ही धुले हुए कोकिंग कोल की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने से उतनी ही सीमा तक कोकिंग कोल के आयात के भी कमी आ जाएगी । नान-कोकिंग कोल उपलब्ध किए जाने से बोयलर की क्षमता तथा प्लांट लोड फैक्टर में भी वृद्धि होगी । इसमें जो ट्रांसपोरेटेशन का सिस्टम है उस पर जो अनावश्यक बोझ पड़ता है यह बोझ भी न पड़ पाए, इस बात को भी दृष्टिगत रखा गया है और उसमें भी कमी आ जाएगी, ऐसा मेरा विचार है ।

जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी और कठिनाई की दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश, जहां तक मैं सोचता हूं, एक अच्छा कदम है, स्वागत-योग्य है और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल है और उस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह बिल उपयोगी साबित होगा। क्योंकि हम लोगों को परिवहन की कठिनाई का सामना करना पड़ता है । आजकल कोयले का खनन सरकार की किसी कंपनी या कारपोरेशन अथवा आयरन और स्टील के निर्माण में कार्यरत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित विद्युत उत्पादन वासी अन्य उपयोग में कार्यरत जो कंपनी है उनको भी कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान की जाय । जिस मंशा और जिस कमी में सुधार को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं, जहां यह अच्छा कदम है वहां दूसरी ओर बहुत कुछ सावधानी और संजीदगी की भी आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी के पास कोल डिपार्टमेंट के साथ साथ श्रम विभाग भी है । इसलिए उस नाजुकता को भी ध्यान में रखेंगे और उन सब बातों पर ध्यान रखेंगे जिनकी वजह से कोल इंडिया लिमिटड पर बहुत कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं । मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां बहुत ज्यादा मात्रा में कोल माईन्स हैं और वह मध्य प्रदेश है । यद्यपि वहां पर प्रचूर मात्रा में कोल है, लेकिन उसका उपयोग जिस ढंग से होना चाहिए और उससे जितना लाभ उस प्रदेश को और अन्य स्थानों को मिलना चाहिए, वह लाभ, वहां वांछित लाभ, प्राप्त नहीं हो पाता है । मैं समझता हूं इसके मूल में कोई कारण है तो वह कारण यह है कि कोल इंडिया में जो अनियमितायें हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता । इस लिए जिन कठिनाइयों का मैंने जिक्र किया है जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं, उनका मैंने विवरण प्रस्तुत किया है । उसको दृष्टिगत रखते हुए यह बिल जो माननीय मंत्री जी लाए हैं यह एक अच्छा कदम है ।

4.00 P.M.

वहां यह भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि कोल इंडिया लिमिटड में जो मनमानी और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर अंकुश लगाया जाय ताकि जिस मंशा से ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उस मंशा की पूर्ति हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI DAVID LEDGER (Assam): I rise to support this Bill and I welcome the decision of the Government to allow private sector participation in the power sector. We art all aware of the acute power shortage in the country today. Power generation, be it coal power or hydel power, has always fallen behind target. Conservation of power has never been possible, Industries have always suffered. Consumers in general have always faced great distress. This has been the regular feature of each of our Five-Year Plans. It is, therefore increasingly felt that public sector alone will not be able to deliver the goods. In view of the prevailing chaotic condition the

decision of the Government to allow private sector participation in the power sector has definitely come as a welcome move.

In the Statement of Obejects and Reasons he Minister has admitted that the major producers of coal and lignite *viz.* the Ccal India Ltd. and the Neyveli Lignite Corporation Ltd. are facing resource constraints and as a result a number *o:* projects could not be taken up. So, the only way *is.* to invite the private sector to the power generation business.

As a matter of fact, there is a gentral disatisfication throughout the country today over the performance of the publij sector. It is not only in the case of coal, it is in the field of other forms of powr generation as well.

The State Electricity Boards today have become a permanent source of embarrasment to the Government a.-; wall as to the people. These State Electricity Board$_s$ .have made the lives of people in some of the States, especially in th North-Eastern States, a pure hell. These Boards are perennially in the red. This is typical of almost all the States. So, the people are just getting fed up. Everybody is saying today that these electricity boards should be handed ower to the private sector. They will run them much more efficiently. 'There will be much more power generation and the people will suffer less. I am saying this because the$_r$e is a general feeling in the country today that there is an acute shortage of power because of mismanagement. corruption and inefficiency. I would not like to take much time of the House because I have already said that the decision of the Government to allow the private sector participation in the power sector is definitely a very good move and that the decision to amend the Coal Mines Nationalisation Act, 1973 is, therefore, justified, because it is the only way to allow the private sector participation in coal mining for the purpose of power generation. I have just referred to the mismanagement in the electricity boards in the matter of power generation. I only wish that the Government gives full consideration to the question of handing over of the sick electricity boards to the Private sector also. It would do a lot of good to the people of the people of the country.

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Dcssi) in the Chair].

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the hon. Minister for having brought the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill, 1992 even though it is a half-hearted measure. "When the coalmines wer na-tionalisd, the expectation was that the production will increase, the cost price will come down and the coal will be available at cheaper rate. But let me say that that expectation has not been fulfilled. If there is failure on the part of the public sector, they should not be afraid of admitting it. As far as coal production per worker in India is concerned, it is the lowest in the world. Our workers are not able to produce one tonne of coal per day but the expenditure is more than Rs. 120. In Australia the cost of production of coal is Rs. 20 per tonne whereas in India it is more than Rs. 200 per tonne because our production per worker is too low in the world. Even the Labour Minister, Mr. San-ma is trying his best to rectify the situation. But he has not suceeded in increasing the production of coal per worker because of the monopoly and trade union activities. These are all hampring the production of coal per worker. Mr. Minister, I would like to suggest that you should link wages with productivity. Then, you would be able to improve the functioning of the coalmines. Sometimes you will have to take unpopular measures in the interest of the people and in the interest of the country.

Regarding the quality of coal, the less said the better it is. Because of the poor quality of coal, the power generation in the country is suffering.

[Shri Vithalbhai M. Patel] When we draw the attention of the Coal India Limited to the poor quality of coal, they blame the poor quality of machinery supplied by BHEL. So the power generation is less. Later on a number of experts have gone into this matter. They said that because of the inferior quality of coal the power stations are suffering. They are not able to produce according to their capacity. Looking into all these things, I think, whatever small step you are taking is one step in that direction. For that you deserve my congratulations.

I know that my State is suffering due to lack of power generation. You are not able to supply them enough coal. The industrialists are suffering. The industrialists are prepared to run the coalmines. You allot them some coalmines because you are not able to supply them their requirements.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI); Mr. Patel, that point *ho,s* already been covered in the Bill. You see it under item (d).."*.. (Interruptions)*... What you say also can be covered by a notification.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: If the Government cannot fulfil their requirements, let the private sector do it. There is nothing wrong in it

May I draw the attention of the Minister to an important issue? When the coalmines were nationalised you have taken away properties of a number of people. You have not paid them compensation till today. The land which you acquired some nineteen years ago, the property which you acquired, you are supposed to pay them compensation, whatever compensation you want to pay, pay them. I know of one instance in the case of the Eastern Coalfields. One widow is running from pillar to post to get the compensation for her land acquired 19 years back. She has not been paid the compensation even after 19 years. Even the Leagl Adviser of the Eastern Coalfields has advised the company either to pay rent or to purchase the property. But they are not paying any rent; nor are they purchasing the property. This is absolute dishonesty. This widow has no money. Otherwise, she would have gone to the court. Now she has either to go to the President or to a Parliamentary Committee to get justice. But that will not give you a good name, Mr. Minister. For God's sake, dispose of, as soon as possible, the cases of compensation which are pending your decision. Otherwise we are getting a bad name.

Lastly, if necessary improve the Bill further. If any private company wants a lease to mine coal, you entertain them. Let there br competition. Without competition, the performance of coal mines, Coal India, is not going to improve. Let the private sector come in. This will help you also in increasing the production. The production of private companies will-be must more than the production of Coal India per worker. So let there be competition.

Thank you.

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले कोयला मंत्री का भाषण इसी सदन में हो रहा था और उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हिन्दुस्तान में मौजूदा जो स्थिति है कोल माइन्स की उसके हिसाब से 30 प्रतिशत ही उनके कोयला खान खदान काम कर रहे हैं और उससे करीब करीब वे 80 प्रतिशत कोयला इस देश को पहुंचा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि सौ से में 30 प्रतिशत के माध्यम से उनका कोयला विभाग आज काम कर रहा है और लोगों को कोयला पहुंचाने की हालत में आज भी वे मौजूद हैं । लेकिन जब मैंने आज यह बिल देखा तो मेरी समझ में नहीं आया कि वे तो कोयला मंत्री आज इस तरह के बिल का समर्थन करने के लिए कैसे आ गए । संगमा साहब बहुत ही काबिल मंत्री हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश मेरे मन में तो कम से कम नहीं है । लेकिन

एक काबिल मंत्री के माध्यम से एक नाकाबिल काम हो तो मन थोड़ा सा शंकित हो उठता है कि आखिर कौन सा ऐसा दबाव उनके ऊपर आया, कौन का ऐसा कारण इसके मन में समाया जिसके चलते इस तरह के बिल को इस सदन में लाने का काम उनके माध्यम से हुआ है । जो अधिकार इसमें देख रहा हूं, जो पावर्स दी गयी हैं वे तो इस देश को उस रास्ते की तरफ ले अलग कर रखी है जिस रास्ते की शुरुआत कोयला विभाग ने सन 1973 में कुमार मंगलम साहब से की थी और जो देश का एक यूनियार्दी सिद्धांत था । सरकारीकरण के माध्यम से हमने देश के लोगों से वायदा किया था कि हमें गरीबी तक इस सरकारीकरण का फायदा पहुंचाने का काम करेंगे । लेकिन जो पावर्स, जो अधिकार इस विधेयक के माध्यम से निजी क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे हैं उनके क्या नतीजे निकलेंगे यह सोचकर मैं थोड़ा हैरान होता हूं । आपने देखा कि इस देश के अंदर जो नयी आर्थिक नीति आयी उसके क्या नतीजे निकले । एक स्कैम से पूरा भारत दुनिया के नक्शे पर गिर सा गया । कितने और दूसरे स्कैम इस तरह के कारणों से बनेंगे, इसके बारे में गम्भीरता से सोचने का समय आज भी आपके सामने मौजूद है और मैं यही गुजारिश करने उठा हूं कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार आप करें । जहां एक ओर आप कहते हो कि इन कामों के लिए कोयला माइंस को दूसरे क्षेत्रों की तरह दिया जाए लेकिन दूसरी ओर इसके नतीजे क्या निकलेंगे . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The fourth one is very important.

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उस पर आ रहा हूं धीरे धीरे करके । उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समर्थन दिया । मुझे खुशी है । आपने राष्ट्रीय हित में यह सवाल उठाया है इसलिए मैं अपने को आज मजबूत स्थिति में पा रहा हूं, बावजूद इसके कि मेरे बायीं ओर दायीं ओर, दोनों ओर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं । लेकिन राष्ट्रीय हित में आपने समर्थन किया है इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am talking about clause 2, sub-clause (4) of the Bill which says: "Such other end use as the Central Government may, by notification, speify."

श्री दिग्विजय सिंह : जी, मैं उसी सवाल पर आ रहा था जिस पर उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा ध्यान खींचा है । मैं कोयला मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप जो यह ताकत दे रहे हैं, जो चौथा प्रावधान है : Such other end use as the Central Government may, by notification, specify.

कल को मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कोई आदमी पावर बनाने के लिए आपसे कोयला ले रहा है और वह बिजनैसमैन अगर वह यह कहता हो अब यह गैस बनाने से या पावर बनाने से जो ज्यादा मेरे पास बच गया उसका अब मैं क्या करूं, वह कह रहा है कि मुझे बाजार में बेचने की इजाजत दो और मुआफ करेंगे मैं बड़े अदब से कह रहा हूं जो पिछले कोल इंडिया के चेयरमैन का रेकार्ड है, मैं तो हैरान था, मैं पटना में घूम रहा था। पता चला कि कोल इंडिया का एक चेयरमैन करोड़ रुपया ले कर जा रहा है बिहार में राज्य सभा का चुनाव लड़ने के लिए । सारे अखबारों में रोजाना छपना था । एक पदाधिकारी आते थे नारायणन वहां पर घूम रहे थ विधायकों को खरीदने के लिए । अगर इस एक बात की ताकात मुझे डर है कि जिस दिन इस तरह का प्रावधान आपसे मांगा गया कि मुझे कोयला बेचने की इजाजत दो अब तो बिजली से ज्यादा कोयला पैदा में कर रहा हूं तो आपके पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको एक सैकण्ड नहीं लगेगा कि उस पर वह दस्तखत न कर दें । तब क्या यह बात सही नहीं होगी कि 1973 के सारे कारनामों को आप बदलने की कोशिश उस माध्यम से करेंगे । नेशनलाइजेशन पूरा

[श्री दिग्विजय सिंह)

ही नेशनलाइज अपने आप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ? इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा इस पर भाषण देने नहीं आया हूं, एक तो फिजा इस देश में बनाने की कोशिश की गई है कि पिछले साल भर से कि हर चीज जो सरकारी क्षेत्र में है वह गलत है, हर चीज का निदान सिर्फ प्राइवेट सैक्टर के अन्दर ही है । निजी क्षेत्र के माध्यम से ही इस देश का उद्धार हो सकता है और टाटा जी को जिस दिन भारत रत्न इस देश में दिया गया उस दिन तो सरकार की नीति और साफ हो गई कि देश के उद्धार करने वाले, इस देश को सम्मानित करने वाले वही पूंजीपति हैं जो इस देश के आज हजारों करोड़ रुपये स्कैम के माध्यम से लेकर चले गए और देश में भी रखते तो मुझे खुशी होती, यह पैसा विदेशों में चला गया ।

मंत्री जी, मैं एक बार फिर आपसे अदब से कहता हूं आप बहुत काबिल मंत्री हैं, होनहार और समझदार मंत्री हैं, देश को आपके हाथों से उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास न हो जिससे यह देश एक बार फिर से यह सोचने को मजबूर हो कि संगमा जी जैसा काबल आदमी भी इस गलत काम को करने के लिए क्यों मजबूर हुआ । इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस बिल के प्रचवधानों को एक बार फिर से समझने की कोशिश हो और आज इतनी जल्दी से इस बिल को पास करने का प्रयास किया जा रहा है, वह काम न हो । मैं आपके अच्छे इरादों पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके अच्छे इरादों के साथ जो शक मेरे मन में है, वह आपके माध्यम से उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं । इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद ।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. Technically, it is a small Bill. It seeks to amend section 3 of Act 26 of 1973. If we go back to 1973 when the Government had nationalised the coal industry, the coal mines the Preamble speaks about the main intention of the Government. "...With a view to reorganise, coordinate and to develop the mining industry on scientific pattern and utilisation of coal resources for the growing requirement of the country". Mr. Vice-Chairman, Sir, I understand the purpose behind the nationalisation of the coal industry but it is sad that whenever anything is nationalised by the Government, the purpose is not achieved because it is often sabotaged by the bureaucracy. I compliment the hon. Minister for bringing forward this Bill and I don't think that it will defeat the purpose of the Preamble of the Nationalisation of Coal Mines Act of 1973. With the announcement of the new Industrial Policy by the hon. Prime Minister, it is pertinent to mention that with the growing demand of the industry the Government also should make a provision to see that the raw-material is supplied the fuel is supplied, the electricity is supplied. And I feel the new Industrial Policy would have been non-workable, if this arrangement was not made by the Government. So I compliment the hon. Minister on this. I urge him to see that coal is denationalised to a particular sector, the private sector only to produce electricity and such other fuel which are required by the industry. Sir, the hon. Minister has brought in item (iii) (4) under clause 2 of the Bill. An objection is raised to this by my hon. colleagues on the ground that the hon. Minister is taking a blank cheque from the Parliament. It will be proper for the Minister to come to the Parliament again as and when he finds it fit to include more industries under this Act. So I feel either the hon. Minister should[1] specify the items or he should come again to the Parliament seeking its approval. I compliment the hon. Minister for including iron-ore and steel in this Bill. As the hon. Prime Minister has mentioned, it is wasteful for our industry that we export our raw material at cheap rates and in turn we lose a lot ' of foreign exchange. For example, in my State we have iron-ore. We export iron-ore at the rate of: 15 dollars a tonne and in return we import steel

at hundreds of dollars a tonne. So this purpose will be met by allowing this coal to be used by the iron-ore and steel producing units.

As I have already mentioned earlier, the preamble says that the purpose of nationalisation was to realise the objective of a socialistio pattern of society, but socialism is not workable, it is outdated. So the mere inclusion of the slogan 'the socialistic pattern of society' within the preamble of the statute will not serve any purpose.

Sir, the hon. Minister has mention-eel' in the Financial Memorandum that he would be requiring more money to strengthen the Coal Controller's Organisation. I think it is not proper for the Minister to add more and more officials to it, but it will be appropriate for the Minister to see that this Organisation is strengthened from the safety point of view. We see many of the coal mines are on fire and it is very difficult to control it. And now the Minister will open many floodgates because now new virgin mines will be given to the private sector. I hope the hon. Minister will see that this private industry has the technology to mine this coal. If there is any eventuality , I don't think they will be in a position to control this fire without having the proper technology. So only if we provide them the technology within the country and strengthen our safety measures and system, it will be much easier for this private sector to see that more and more fuel, electricity, is generated.

With these few submissions I support the Bill. I again request the hon. Minister to reconsider item (iii) (4) of clause (2) which he has proposed to incorporate in the Act and I wish him all the best.

श्री दयानन्द सहाय (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में परिस्थिति और समय बदलने के साथ-साथ उस देश में नियम बदलते हैं, कानून बदलते हैं। हमारे देश में भी हमारा विधान 75 बार बदल चुका है, एमेंड हो चुका है और यह कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, 1973 के एक सबक्लाज को बदलने में हमारे कई माननीय सदस्यों को आपत्ति है। उनको आशंका है कि क्यों कांस्टीट्यूशन के प्रिअम्बल की दुहाई दी जा रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कोयला मंत्रीजी को कि आज की परिस्थिति में उसमें जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए वह यह अमेंडमेंट लाए। अगर मुझसे कहा जाता तो बिना यह अमेंडमेंट लाए हुए भी सारा काम हो सकता था, लेकिन मंत्री अपनी ब्यूरोक्रेसी के दबाव में कहें या शायद कोई क्रिटिसाइज (आलोचना) न करे, इसलिए अमेंडमेंट यह लाए हैं वरना कोयले की वाशरी तो टाटा कम्पनी की बहुत पहले से चल रही है। कोयला माइन भी मैं उनका अलग से चल रहा है। कोयले में वाशरी करने के लिए तो सिर्फ कांट्रेक्ट देना है। पर, इनके सेक्रेटरी ने भाषण दिया था——

"It is like a laundry; they could have hired it." Any number of workers.

महोदय, मुझे कोयला मिनिस्टर से शिकायत है कि इन्होंने अपनी परिस्थिति तथा दिक्कतों की जानकारी सदन को डिटेल में, तफसील में नहीं दी। इनकी दिक्कत क्या है? मैं इनकी दिक्कत दो-तीन बात रहा हूं। कोल माइनिंग करने के लि इनको बिजली नहीं मिलती है। दिन में 30 बार, 40 बार ट्रिपिंग होता है और जो बिजली कठिनाईयां हैं याने नेशनलाइज्ड, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज जिनको यह कोयला देते हैं, वह इनको पैसा नहीं देते, बिजली की बात तो दूर है। क बार ट्रिपिंग होती है तो दो घंटे के लिए माइन बंद हो जाती है, 60 फीट या 70 फीट नीचे जो काम करने वाला मजदूर है उसको बाहर निकालना होता है। अगर इनके पास बिजली नहीं होगी तो इनकी कोयला खदान बंद होगी। यह नंबर एक दिक्कत है। नम्बर दो, इनके यहां जो कोयला अपने देश में खदानों से निकल रहा है, उसमें 40 परसेंट ऐश और मड है, पत्थर और डस्ट है। देश के एक कोने

[श्री दयानन्द सहाय]

से दूसरे कोने तक इस तरह का कोयला ढोया जाता है रॉ कोल कहते हैं और फिर उसको मिलता है 60 परसेंट यानि ग्राहक को 60% अच्छा कोयला मिलता है । हम भाड़ा भी अधिक देते हैं और फिर उसके ऊपर एक आर्थिक देशद्रोह का काम मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश का कोयला खराब है, यह कहकर अच्छा कोयला इम्पोर्ट किया जाता है विदेशों से । पांच मिलियन टन कोयला स्टील अथोरिटी इम्पोर्ट कर रहा है । इसके अलावा जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु पावर स्टेशन को कहा गया था कि तुम भी आस्ट्रेलिया से कोयला मंगवा लो । अब अपने देश में 200 मिलियन टन कोयला बने, खदान से निकाला जाये और फिर भी हमारे देश में आस्ट्रेलिया से कोयला आये ? क्या विडम्बना है ।

महोदय दुनिया का सबसे अच्छा कोयला हमारे झरिया धनबाद और बंगाल में है । हमारे देश में उसके डवलपमेंट पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है । कोल मिनिस्टर साहब जब प्लानिंग कमीशन से कहते हैं कि मुझे 500 करोड़ रुपया दो, सौ वाशरी बैठाऊंगा इनको पैसा नहीं मिलेगा । स्थिति यह है कि न आप कीजिए न प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए लेकिन विदेश से कोयला मंगाने पर किसी को आपत्ति नहीं है जबकि यह कोयला 100 डालर प्रति टन तक विदेशी मुद्रा से आता है । दिल्ली में बैठे हुए दलाल जिनको पांच दस डालर कमीशन मिलता है वह तो चाहेंगे समाजवाद जिंदाबाद रहे इस देश में कभी भी प्राइवेट सेक्टर काम न करे और सरकार के पास पैसा न हो ताकि वह काम कर सके । इस परिस्थिति में इस बात को सदन के सभी सदस्यों को हमारे कोल मंत्री जी को बतानी चाहिए थी कि वे गलत ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं पत्थर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरे पावर के बिना उनका माइन नहीं चल रहा है तीसरे वे यहां 200 मिलियन टन कोयला खनन करते हैं और सिर्फ 10 मिलियन टन वाशिंग करते हैं । मेरा सुझाव है कि यह सारा काम आप खुद करें अगर न करें तो ज्वाइंट सेक्टर करे ज्वायंट सेक्टर न करे तो प्राइवेट सेक्टर को करने दें । मैं भी यही सिफारिश करूंगा कि कोयले के एन्डयूज के लिए दो चीजें हों—वाश किया हुआ कोयला इन्हीं का होना चाहिए, कोल इंडिया का होना चाहिए और बेचने का अधिकार भी सिर्फ इनको होना चाहिए, वाश कोयला बेचने का अधिकार वाशरियों के मालिक को न दें और दूसरा यह कि पावर स्टेशन केप्टिव पावर, इनका होना चाहिए । ये हर वाशरी के साथ इनका अपना या ज्वाइंट वेंचर या प्राइवेट सेक्टर में 10 मेगावाट, 20 मेगावाट का पावर स्टेशन तथा वाशरी बैठना चाहिए । पूर्ण रूपेण पावर इनको मिले ताकि इनकी माइनिंग का काम सुलभ हो सके ।

महोदय, आज तक मुझे एक समाजवादी ऐसा नहीं मिला, जो यह कहे कि घाटे वाली खदानों को बन्द करो । इनके यहां 100 माइन ऐसी हैं जहां एक टन कोयला, खदान, कर ने में इनको 1200/- रुपये लगते हैं और 300/- रुपए में इनको यह कोयला बेचना पड़ता है । कोई भाई का का लाल, कोई यूनियन वाला यह नहीं कहता यह देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश की जो पूंजी है, जो बजट है वह सेक्रीसिंग है, लेकिन वे उसे बनिया की दुकान समझते हैं, जितने यूनियन वाले हैं वह तो कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो । देश का कंज्यूमर भी है, देश भी है, टैक्स देने वाले भी हैं, इन सबका हित देखने के लिए कोई नहीं सोचता है । मैं चाहता हूं कि हमारे कोयला मंत्री अपनी सारी दिक्कतें सदन के सामने रख दें कि सौ-सौ माइन्स में यह आवश्यक लेबर रखे हुए हैं, 1200/- रुपए, 1506/- रुपए प्रति टन मजदूरी देते हैं और 300/- रुपए साल में माल बेचते हैं । किसका घाटा होता है ? देश के सभी लोगों का । जिस दिन यह सवाल उठेगा, कोयला मंत्री कहेंगे हाथ मजबूत होगा कि जो मेरी अनइकनॉमिक माइन्स हैं, उनको किनारे कीजिए । यूनियन को कह दीजिए, लेबर यूनियन को कि तुम चलाओ, हमारे पास पैसा नहीं है कि 1500 रुपया टन प्रोडक्शन दूं और 300 में बेचूं ।

इन शब्दों के साथ मैं कोयला मंत्री को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं कि वे जो कर रहे हैं यह देश

काल और परिस्थिति के अनुसार ठीक कर रहे हैं यह अमेंडमेंट करें, लेकिन एक मेरा सजेशन है कि जो एण्ड प्रोडक्ट है, इसको बेचने पर इनका अधिकार रहना चाहिए यह न हो कि प्राइवेट सैक्टर को दे दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सब क्लास 4 के बारे में आपकी क्या राय है

श्री दयानन्द सहाय : सब क्लास पर ही कह रहा हूं कि एण्ड प्रोडक्ट पर इनका अधिकार रहना चाहिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने समर्थन ही किया न ।

श्री दयानन्द सहाय : मैं इनको अधिकार ज्यादा दिलाना चाहता हूं ।

श्री सप्रिय गौतम : समर्थन तो सारे हम कर रहे हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MIN ISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Mr. Vice-Chairman, Sir. I am grateful to all the hon. Memb ers who have participated in this short debate and also extended sup port to this Bill. The necessity for bringing this amendment Bill has been spelt out in the objects of the Bill and initial remarks by the Deputy Minister while commending this Bill for the consideration of the House. The Eighth Five Year Plan envisages an additional power generation to the tune of 30,538 MW. Out of the 30,538 MW of additienal power to be generated during the Eighth Five Year Plan as much as 20,156 MW is to b$_e$ generated from the thermal sector, that is, coal and lignite.

If 20,156 MW of additional power is to be generated, during the Eighth Five Year Plan then the demand for coal by the end of the Eighth Five Year Plan will be 311 million tonnes. But as on today we will be able to produce only 298 million tonnes. So, by the end of the Eighth Five Year Plan there will be a gap of 13 million tonnes of coal. This is one aspect. The second aspect is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What is the gap?

SHRI P. A. SANGMA: The demand will be 311 million tonnes but our production will be 298 million tonnes. So the gap will be 13 million tonnes of coal by the end of the Eighth Plan.

If coal is to be supplied for generating 20,156 MW then the total amount of money which is required by us. by our Department, Coal India Ltd.. Singareni, Neyveli altogether is coming to the tune of Rs. 19,374 crores. This is the money required which we have projected to the Planning Commission. But, ultimately, the Planning Commission has brought it down to Rs. 11,320 crores. Of course, it is yet to be finalised.

THE VICE-CHAIRMAN: That means, it is le,ss than what they are giving now. Because what I have seen is. Rs. 2000 and odd crores you are getting for Coal India and Rs. 600 crores you are getting for lignite for the year.

SHRI P. A. SANGMA: I am talking about the Eighth Plan. I am not going by years. I am talking about the entire Eighth Plan.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): They want to reduce even what they are giving now. (Interruptions). I wanted it to be clasi-fied.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, the Plan allocation is going to be Rs 11.320 crores as against our projected demand of Rs. 19,374 crores. So we have a clear-cut gap of Rs. 8,000 crores in order to generate 25,156 MW. Now, even Rs. 11,320 crores which more or less will be approved by the Planning Commission for the Eighth

[Shri P. A. Sangma] Five Year Plan, the budgetary support that is given by the Government of India is very very minimal. At the time of nationalisation we used to get 100 per cent budgetary support and till even 1985 it used to be at least 90 per cent budgetary support, But this year our budgetary support has come down to just 19 per cent. Taking all these factors into account we were really in difficulty. We had a lot of discussions among ourselves in the Ministry and we have only three alternatives before us. One alternative is; if I am required to produce 311 million tonnes of coal by the end of the Eighth Five Year Plan then I must get the money that I require from the Government of India as budgetary support which is not available. The second alternative is that the power stations or the consumers who will take coal from us, they will give the money to us to develop new mines and with their money we will develop new mines and supply them coal. That is the second alternative available to us and we know that this is not possible because you know even tcday I have got Rs. 18,000 crores as arrears from our consumers. So there is no question of the consumers giving us advance money for developing new coal mines. And the third alternative is that we lease out some specific mines purely for captive purposes—"we require so much of coal, we do not have the money to develop the mine so you develop it". This is the most acceptable solution that we found and it is precisely because of this reason I have come to this august House to seek this amendment. I can assure the House that the Government of India has no intention as of now to denationalise the mines.

There is no proposal at all. There is no such proposal under the consideration of the Government. Those who are going to have the lease of new mines, it is going to be purely for end-use purposes. They cannot and they will not be allowed to use that coal for some other purpose or to market it or to sell it to others. Mr. Dayanand Sahay made a very emphatic point, that is, the marketing part of it. All the coal will be with the Coal India Limited and' we are not going to give it to others. It is only for captive purposes for their end-use ' that we come to seek this amendment. The reasons I have already explained.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister, if you had said like that, I would have been very happy. But you have crossed the scope which gives rise to some doubts. So you must make it clear that it is for this purpose that you have taken very wide powers by issuing this notification.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, if everything was said' before, then the Minister would have nothing to speak after the debate. So we did not want to give all these figures. The second aspect of the amendment is to allow the setting) up of washeries by the private sector. On the floor of. this House there was no question, there was no way, when coal was discussed and the question of quality was not addressed. The maximum complaint that we get in the Ministry from the Members of Parliament and' in the discussions that take place on the floor of both the Houses of Parliament is regarding the quality of coal. I have very frankly admitted both in the Lok Sabha as well as this august House that unless and until we are able to supply beneficiated coal, the complaint on quality will be there. We will not be able to give quality coal. The only way to supply quality coal is to beriL-ficiate the raw coal and for that purpose carries the question of resources. We do not have the money with us. Therefore, we are gaing to allow the private investment as far as setting up of washeries is concerned so that we can achieve two things— one is that we are able to satisfy our consumers on quality and secondly we bring down the pressure on transportation. As some of the hon. Members have rightly pointed! out, it so happens that sometimes the raw coal

"which is. going to the consumers contains 25 per cent to 30 per cent ash and if the raw coal is washed and transported, then the pressure on railways will also come down and we will be able to supply and transport more. As the position stands today, the Railways are having a lot of problems in transporting materials goods, etc., and, therefore, sometimes even if we have the coal with us, because of transport problems we are not able to satisfy the demand. And I have the details of what type of washeries we are contemplating; I do not know by what time. I don't think it is wise for me to waste the time of the House in giving these details. We will notify these details. There are a few individual points that were raised.

Mr. Hanumanthappa has referred to the closure of a thermal plant four days after my departure from Bangalore an:]' where I had given an assurance that coal would not be a problem. Coal is available. I am given to understand, Sir, that 1he power plant was shut down not because we did not supply coal. The House is aware that from the 1st of October, 1991, we have introduced the cash-and-carry system. We do not suoply coal any more on credit. Their credit tod'ay stands at Rs. 20 crore:; and perhaps it was because of this reason that there has been a temporary suspension of supply of coal.

As far as Tamil Nadu is concerned—my friend has asked about Tamil Nadu—all the three thermal power stations in Tamil Nadu are linked to Singrauli Coal Field ani(the Western Coal Field and it will continue to be so. There is no question of the existing power plants having to depend on the private mines. No power plants will be made to depend on the private mines because I have explained that the private mines will be absolutely for the end'-use and for captive purposes. Therefore, the existing arrangements fo-- all the thermal plants all over the country will, continue. With these few words, Sir I once again thank the hon. Members for having given support and given us the ideas and I request that the Bill be taken into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): I shall now put the motion to vote. The question is:

> That the Bill further to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Mr. Madhavan, are you moving the amendment?

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I shall just ask one question. The company has been defined in the principal Act. It includes private, public and foreign companies. I would like to know whether the Government is going to allow the private limited companies and also the foreign companies to explore the coal mines.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, as of now, Section 5 of the Mines Act debars investment in the coal sector. Therefore, the investment that we are talking of, as of today, is intended only for domestic investment and' not for foreign investment. If foreign investment is to be brought in to the mining sector, then Section 5 of the Mining Act has to be amended. Not before that.

SHRI S. MADHAVAN: In view of what the Minister has said, I do not want to move the a mendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): Now, I will put Clause 2 to vote. The question is:

[Shri Jagesh Desai] That Clause 2 stand part of the Bill. *The motion was adopted. Clause* 2 *was added to the Bill. Clause* 1, the *Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में आप बिजली को देने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं । मेरा सवाल यह है कि क्या जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं जो अभी कैप्टिव और कैप्टी सिस्टम में पैसा देकर आपको पैसा देकर अ.पसे बिजली ले रहे हैं वह अगर चाहे तो अपने स्टेट्स में जहां कोयल. है वहां पर उनको भी क्या लीज दी जाएगी या नहीं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या कोयले के संरक्षण के लिए परमिशन दी जाएगी कि वे कोयले का खनन कर सकें और अपने बोर्ड चला सकें । इसका ऐश्योरेंस आप हाउस को देंगे ?

SHRI P. A. SANGMA: If the private power sector is entitled to get captive mining, it automatically follows that the existing power stations of the Electricity Boards, if they won the lease, will also be entitled under this amendment.

Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MASSAGE FROM THE LOK SABHA

The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Amendment Bill, 1992

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Amendment Bill, 1992, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st July, 1992." Sir, I lay the Bill on the Table. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI): The House now stands adiourned till eleven of the clock on Wednesday, the 22nd July, 1992.

The House then adjourned at forty-nine minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 22nd July, 1992.